



# ACHIEVERS IAS ACADEMY

## SUMMARY OF THE HINDU FOR BPSK EXAMINATION

**HINDI**

DATE

**29/11/2023**

## THE HINDU National

### ➔ सुरंग का संकट समाप्त, फंसे हुए सभी श्रमिकों को बचाया गया

उत्तरकाशी में ढही सिल्कयारा सुरंग से 17 दिन बाद 41 मजदूर बाहर निकले।

सुरंग के बाहर खुशी का माहौल था।

एनडीएमए उन्हें सुरंग के बाहर ले आया.उन्हें 48 से 72 घंटे तक निगरानी में रखने की सलाह दी गई है।सीएम धामी ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए ₹1 लाख मुआवजे की घोषणा की है।

रैट होल खनिकों का उपयोग क्षैतिज रूप से 55 मीटर मलबे को खोदने के लिए किया गया था, मंगलवार को लगभग 12 रैट होल खनिकों ने अंतिम 10 मीटर की खुदाई की। रैट होल खनन एक ऐसी तकनीक है जिसे 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि यह अभ्यास खतरनाक था।

चूहा खोदने वाले खनिक 4-5 फीट तक खुदाई करते थे। कोयला खदानें खोदना और कोयला निकालना बहुत खतरनाक है।

कई सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने बचाव प्रयासों में भाग लिया।

### ➔ सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर से हिंसा पीड़ितों का अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि मणिपुर हिंसा के अज्ञात शव और अन्य पहचाने गए शव जो अनिश्चित काल के लिए मुर्दाघर में रखे गए हैं, वे सम्मानजनक विदाई के पात्र हैं और राज्य को उनके अंतिम अधिकारों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मई से अब तक मुर्दाघर में 169 पहचाने गए शव पड़े हुए हैं।

अदालत द्वारा नियुक्त गीता मित्तल समिति ने कहा है कि नागरिक समाज समूह दोनों राज्यों के बीच शवों को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

### ➔ बिक्री के लिए 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक

सरकार बुधवार को देश भर में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहले दौर की कार्रवाई शुरू करेगी, जिसमें 20 ब्लॉकों पर नीलामी होगी। खान एवं मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नीलामी ऑनलाइन होगी और निविदा दस्तावेजों की बिक्री बुधवार से शुरू होगी।

“खनिज ब्लॉकों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि का विवरण। इसे MSTC नीलामी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सकता है," इसमें कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की ओर हमारे परिवर्तन का समर्थन करेगी।"

महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।



Critical minerals for which India is 100% import-dependent

Mineral	Major application
Lithium	Rechargeable batteries, ceramics
Cobalt	Rechargeable batteries and superalloy
Nickel	Stainless steel, superalloys, rechargeable batteries
Vanadium	Alloying agent for iron and steel, batteries
Niobium	Steel and superalloys, construction, transportation
Germanium	Fiber optics and night vision applications
Rhenium	Superalloys, aerospace and machinery use
Beryllium	Alloying agent in aerospace and defense industries
Tantalum	Electronic components, mostly capacitors and in superalloys
Strontium	Aluminium pigments and fillers, glass, magnets

Source: A report on Unlocking Australia-India Critical Minerals Partnership Potential by Australian Trade and Investment Commission, July 2021/ Critical Minerals of India report

➔ **दूत नेकहा, इजराइलगाजा परबमबारी फिरसे शुरूकरेगा, बंधकोंको रिहाकिया जाएगा, युद्धविराम खत्महोगा।**

भारत में इजराइल के राजदूत नूर गिलोन ने कहा कि बंधक सौदा पूरा होते ही इजराइल गाजा पर बमबारी फिर से शुरू कर देगा।

उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करेगा।

“जब तक वे बंधकों को रिहा करना जारी रखेंगे, हर दस बंधकों में से एक दिन में बंधकों की अदला-बदली हो जाएगी।

➔ **सुप्रीम कोर्ट पैनल ने मणिपुर पीड़ितों पर रिपोर्ट सौंपी**

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने मंगलवार को "मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि" पर एक रिपोर्ट अदालत को सौंपी।

रिपोर्ट में मारे गए और पहचाने गए 169 लोगों के परिवारों को दिए गए अनुग्रह मुआवजे के विवरण का उल्लेख है।

मारे गए 166 नागरिकों में से 98 कुकी ज़ो समुदाय से हैं जबकि 67 मैती समुदाय से हैं।

3 मई से 7 अक्टूबर के बीच हुई हिंसा के आंकड़ों से पता चलता है कि आधे से भी कम पीड़ितों के परिवारों को ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच मुआवजा मिला है। जबकि मैतेई समुदाय से एक सहित 38 परिवारों को मुआवजा मिला है।

➔ **विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए: मंत्रालय**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 20 लाख लोगों ने भाग लिया।

## दुनिया

### ➔ इज़राइल-हमास संघर्ष विराम समझौते की अवधि बढ़ने से और अधिक बंदी मुक्त होंगे

फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले में इज़रायली बंधकों के एक नए समूह को मंगलवार को रिहा किया जाना था, क्योंकि इज़रायल और हमास ने एक-दूसरे पर विस्तारित संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इज़राइल और हमास पर इस बात का दबाव है कि वे व्यापक लड़ाई में वापस न लौटें।

फिलहाल अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में दोहा (कतर) में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। इज़रायली नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि हमास को कुचलने का उनका अभियान फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में यथासंभव अधिक से अधिक बंधक प्राप्त करने के बाद फिर से शुरू होगा।

### ➔ प्राचीन मूर्तिकला पर विवाद के कारण सुनक ने ग्रीक पीएम के साथ बैठक रद्द कर दी

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संग्रहालय में प्राचीन मूर्तिकला घरों पर उनकी टिप्पणी पर सोमवार को ग्रीक प्रधान मंत्री क्यारीकोस मित्सोकातिस के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी। इसके बजाय श्री मित्सोकातिस को ब्रिटेन के उप प्रधान मंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

पार्थेनन मूर्तिकला या एल्लिन मार्बल को 1816 में थॉमस ब्रूस से ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा लाया गया था, जो उस समय ब्रिटिश राजदूत थे। संरचना का एक हिस्सा अभी भी एथेंस में है।

आलोचकों ने दावा किया है कि थॉमस ब्रूस (लॉर्ड एल्लिन) ने संरचना चुरा ली थी। हालाँकि ब्रिटिश संग्रहालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उनका अधिग्रहण "पूरी तरह से कानूनी" था।

**Elgin Marbles that is in British Museum.**



### ➔ शी का कहना है कि चीन को विदेशी फॉर्म राइट और आईपी की रक्षा करनी चाहिए

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकार और बौद्धिक संपदा के लिए अधिक सुरक्षा का आदेश दिया है, राज्य मीडिया ने मंगलवार को रिपोर्ट दी, क्योंकि बीजिंग क्रैकडाउन और बीमार अर्थव्यवस्था से डरी हुई विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए काम कर रहा है।

श्री शी ने इस महीने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक शीर्ष शिखर सम्मेलन में एक लिखित भाषण में निवेश के लिए आमंत्रित किया, "विदेशी कंपनियों के लिए चीन में निवेश और संचालन को आसान बनाने के लिए हार्दिक उपायों" का वादा किया।

## ➔ बिडेन के बाद, अधिक विश्व नेताओं ने संकेत दिया कि वे सीओपी 28 को छोड़ सकते हैं

पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी 28) 28 नवंबर से शुरू होगा और 12 दिसंबर को समाप्त होगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) कर रहा है।

पीएम मोदी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को हिस्सा लेंगे। जो बिडेन और सीरियाई राष्ट्रपति जैसे कई विश्वनेताओं ने संकेत दिया है कि वे इसमें भाग नहीं लेंगे।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया है कि जो बिडेन की अनुपस्थिति का कारण इजराइल हमलास युद्ध है। यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू वार्ता में भाग लेंगे या नहीं।

## ➔ चीनी नौसेना के जहाज संयुक्त अभ्यास के लिए म्यांमार पहुंचे

चीनी नौसेना के तीन जहाज अपनी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए म्यांमार पहुंचे हैं।

## संपादकीय

### ➔ कार्रवाई का समय

#### सीओपी 28 को अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना चाहिए

संपादकीय 28 नवंबर से दुबई में शुरू होने वाले सीओपी 28 के बारे में है। इसमें करीब 190 देशों के विश्व नेता हिस्सा लेंगे..

दुनिया के सामने वर्तमान चुनौती बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की है। लेकिन यह बहुत असंभावित लगता है. संयुक्त राष्ट्र की एक हालि या रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश आशा वा दीपरि स्थितियों में भी इस सदी के अंत तक दुनिया 2.5 डिग्रीसे 3 डिग्री से ल्सियस तक गर्म हो जाएगी।

जलवायु वित्तपोषण के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तपोषण करने पर सहमति बनी है। इस संबंध में कुछ प्रमुख मुद्दे जो यहां होने जा रहे हैं वे हैं: ग्लोबल स्टॉकेट का निष्कर्ष और हानि और क्षति निधि का संचालन।

### ➔ एक नॉन-स्टार्टर

#### न्यायाधीशों के लिए अखिल भारतीय सेवा में उच्च विविधता सुनिश्चित होनी चाहिए

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के भाषण के दौरान सिविल अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन का प्रस्ताव रखा। इससे पहले इस प्रस्ताव को 15 में से 13 उच्च न्यायालयों ने खारिज कर दिया था।

संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के निर्माण का प्रावधान करता है और इस प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत के साथ राज्यों की परिषद द्वारा अपनाने की आवश्यकता है।

एआईजेएस सिविल सेवा परीक्षा के समान होगा।

संपादकीय में कई बाधाओं के बारे में बात की गई है, जैसे कई लोग निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं।

